

4 विविध समाचार

आईटी हार्डवेयर पीएलआई 30 अगस्त तक

सोम लेले

नई दिल्ली, 31 जुलाई

केंद्र सरकार ने सोमवार को आईटी हार्डवेयर के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत लाभ के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 अगस्त कर दी है। यह योजना लैपटॉप, टैबलेट, ऑल इन वन पीसी, सर्वर और एज कंप्यूटिंग डिवाइस जैसे आईटी हार्डवेयर के लिए लाई गई है।

मई में अधिसूचित संशोधित आईटी हार्डवेयर पीएलआई योजना में स्थानीय रूप से विनिर्मित आईटी उत्पादों की बड़ी बिक्री पर 9 प्रतिशत

का प्रोत्साहन दिया जाता है, जिससे इस क्षेत्र में निवेश आकर्षित किया जा सके। शुरुआत में इस योजना के शुरु होने के 45 दिन के भीतर आवेदन का वकत दिया गया था।

इस योजना के तहत बजट आवंटन दोगुने से ज्यादा बढ़ाकर 17,000 करोड़ रुपये कर दिया गया, जो पहले की योजना में 7,325 करोड़ रुपये था। सरकार के अनुमान के मुताबिक नई योजना से 75,000 प्रत्यक्ष नौकरियों के सृजन की संभावना है। संशोधित योजना की आधिकारिक अधिसूचना 29 मई को जारी की गई। पीएलआई योजना वैश्विक कंपनियों को अधिकतम

4,500 करोड़ रुपये, हाइब्रिड (वैश्विक व घरेलू कंपनियों) उत्पादन मॉडल को 2,250 करोड़ रुपये और घरेलू कंपनियों को 500 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन मुहैया करा सकती है। यह प्रोत्साहन 2022-23 आधार वर्ष पर विनिर्मित वस्तुओं की बड़ी हुई बिक्री पर निर्भर होगा। अब तक इस महीने की शुरुआत में की गई घोषणा के मुताबिक ह्युलटि पैकर्ड इंटरप्राइजेज (एचपीई) सर्वर विनिर्माण केंद्र को इस योजना के तहत लाभ को मंजूरी दी गई है। नई योजना कुछ वैकल्पिक वस्तुओं के स्थानीयकरण को अतिरिक्त प्रोत्साहन देती है।

राजकोषीय घाटा 25.3 फीसदी

रुचिका चित्रवंशी

नई दिल्ली, 31 जुलाई

चालू वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही में केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा 4.5 लाख करोड़ रुपये रहा, जो बजट अनुमान का 25.3 प्रतिशत है। लेखा महानियंत्रक (सीजीए) की ओर से जारी आंकड़ों से यह जानकारी मिली है। पिछले साल की समान अवधि के दौरान राजकोषीय घाटा बजट अनुमान का 21.2 प्रतिशत था।

अप्रैल-जून 2023 के दौरान ज्यादा राजकोषीय घाटे की वजह पूंजीगत व्यय और राज्यों को त्वरित कर हस्तांतरण है। विशेषज्ञों का कहना है कि गैर कर राजस्व में तेज बढ़ोतरी से इसकी भरपाई हो सकती है। सीजीए के मुताबिक वित्त वर्ष के पहले तीन महीने के दौरान कुल गैर कर राजस्व 1,54,968 करोड़ रुपये या बजट अनुमान का 51.4 प्रतिशत रहा है, जो पिछले साल की समान अवधि के दौरान 23.1

राजकोषीय गणित		(बजट अनुमान के प्रतिशत में)	
	अप्रैल-जून 23	अप्रैल-जून 24	
शुद्ध कर राजस्व	26.10%	18.60%	
गैर कर राजस्व	23.10%	51.40%	
राजस्व व्यय	24.20 %	22.00%	
पूंजीगत व्यय	23.40 %	27.80%	
राजकोषीय घाटा	21.20%	25.30%	
स्रोत: लेखा महानियंत्रक			

प्रतिशत था। लाभांश और मुनाफे से गैर कर राजस्व 105 प्रतिशत बढ़ा है, और इसमें 91,000 करोड़ रुपये जुड़े हैं।

इक्रा लिमिटेड में मुख्य अर्थशास्त्री और हेड-रिसेस एंड आउटरीच अदिति नायर ने कहा, 'बजट अनुमान की तुलना में

रिकॉर्ड पर क्रेडिट कार्ड

बीएस संवाददाता

मुंबई, 31 जुलाई

जून महीने में चलन में क्रेडिट कार्डों की संख्या नए रिकॉर्ड पर पहुंच गई। मई के 87.4 अरब की तुलना में जून में इसकी संख्या बढ़कर 88.7 अरब हो गई है। हालांकि जून में क्रेडिट कार्ड से व्यय घटकर 1.37 लाख करोड़ रुपये रह गया, जो मई में 1.40 लाख करोड़ रुपये था। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी हाल के आंकड़ों के मुताबिक एचडीएफसी बैंक 1.835 करोड़ कार्डों के साथ पहले स्थान पर बना हुआ है, उसके बाद एसबीआई कार्ड 1.734 करोड़, आईसीआईसीआई बैंक के कार्ड 1.48 करोड़ और एक्सिस बैंक के कार्ड 1.25 करोड़ हैं। परिणाम घोषित करने के बाद एचडीएफसी बैंक ने कहा कि बैंक ने अप्रैल जून तिमाही में 15 लाख कार्ड जारी किए हैं, जबकि उसके कार्ड से व्यय में पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 30 प्रतिशत और पिछली तिमाही की तुलना में 10 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है।

पीएम जनधन की सफलता की कुंजी मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी

शाइन जैकब

चेन्नई, 31 जुलाई

महिला सशक्तीकरण भूमिका निभाने वाली दो सरकारी योजनाओं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) और प्रधानमंत्री जनधन योजना (पीएमजेडीवाई) में सकारात्मक सहसंबंध है। भारतीय स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक जिन राज्यों में मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी कम है, वहां महिलाएं पीएमजेडीवाई से कम लाभान्वित हैं।

अभी पीएमजेडीवाई से करीब 55 फीसदी महिलाएं लाभान्वित हैं। हालांकि मनरेगा में महिलाओं की राष्ट्रीय भागीदारी 57.4 फीसदी थी। रिपोर्ट के अनुसार ज्यादातर बड़े राज्यों में मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी 33 फीसदी से अधिक है जबकि कुछ राज्यों में राष्ट्रीय औसत से कम है। अन्य सरकारी आंकड़ों के अनुसार मनरेगा में महिलाओं की भागदारी वाले शीर्ष राज्यों केरल (89.82 प्रतिशत), पुदुच्चेरी (87.48 प्रतिशत), तमिलनाडु (86.41 प्रतिशत), गोवा (78.4 प्रतिशत), राजस्थान (68.17 प्रतिशत) और पंजाब (66.55 प्रतिशत) हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक

पीएमजेडीवाई वाले शीर्ष राज्य तमिलनाडु, राजस्थान, कर्नाटक और केरल हैं।

यह रिपोर्ट एसबीआई के समूह प्रमुख आर्थिक सलाहकार सोम्या कान्ति घोष ने तैयार की है। रिपोर्ट के अनुसार, 'पीएमजेडीवाई का ध्येय अलग-थलग पड़े वगों – कमजोर वगों और कम आय समूहों विशेषकर महिलाओं तक वित्तीय सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करना है। अभी पीएमजेडीवाई में महिलाओं की संख्या 55 प्रतिशत है। महिला लाभार्थियों के राज्य-वार आंकड़ा से जानकारी मिलती है कि इन दोनों योजनाओं में महिलाओं के राष्ट्रीय औसत से अधिक भागीदारी दक्षिण भारत के राज्यों की है।

एसबीआई की यह रिपोर्ट तब आई जब भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में जानकारी दी है कि मार्च, 2023 में समाप्त हुए साल में महिला ग्राहकों के कुल जमा में 20.5 फीसदी की बढ़ोतरी हुई। ग्रामीण क्षेत्र से जमा राशि में महिलाओं की जमा राशि भी बढ़ चुकी है। यह महामारी के बाद के दौर में बढ़ी है। यह वित्त वर्ष 19 (महामारी से पहले के वर्ष) में 25 फीसदी थी जो वित्त वर्ष 23 में बढ़कर 30 फीसदी हो गई है।

क्षेत्रीय मंडियों के भाव

मुंबई
अनाज-दाल : गेहूँ लोकवन 3200/3500, शराबती 3400/3500, थाना मिल 2600/2650, चावल: परमल वंड 3100/3300,कोलम (कर्नाटक) 5600/ 5700, कोलम (नागपुर) 5500/5800, मंस्सरी 3100/3200, दाल : राजमां चित्रा 12600/ 13000, राजमां ब्राजील 11600/ 12400, राजमा इथियोपिया 11400 /11800, मसूर 5600/5625, उड़द एफएस्क्व 8050/8060, उड़द एस्क्व 8500/8510, अहरर लेमन 9900/9950, सरफा (जीएसटी अतिरिक्त) चांदी (किलो): हाजिक 73700, हिलोवर 73800, कच्ची 72100, सोना (प्रति दस ग्राम): बार 59750, स्टैंडर्ड 59500, (23 कैरेट) &, आभूषण (22 कैरेट) 54800, अलौह-धातु (किलो): कॉपर सी स्क्रैप 730, कॉपर एच स्क्रैप 720, कॉपर आरमेचर 706, कॉपर शोट कटिंग 518, ब्रास यूटेन्सिल स्क्रैप 491, एल्यू. यूटेन्सिल स्क्रैप 170, गुन मेटल स्क्रैप 520, ब्रास हनी 500, कॉपर बिलेट्स &, एल्यू. इंगट 207, ज़िंक इंगट 225, लेड इंगट 185, टिन इंगट 2420, निकिल केथड 1843, कॉपर सीसी रॉड 775 कौटन यार्न (किलो): कांडेड वायर: (10/1) &, (40/1) 245/250, (46/1) 255/260, (60/1) 260/265, देशी घो (प्रति लीटर): अमूल 580, विजया 640, पारस प्रौ. &, कुण्णा 495, गोकुल 590, परम प्रौ. 530, मधु सुदन 530, सोमेट (50

लालमिचं एम्पी 23500/27000, चाय (किलो): असम डस्ट 200/280, असम मामरी 190/310, साउथ 140/180, सरफा (जीएसटी अतिरिक्त) चांदी (किलो): हाजिक 73700, हिलोवर 73800, कच्ची 72100, सोना (प्रति दस ग्राम): बार 59750, स्टैंडर्ड 59500, (23 कैरेट) &, आभूषण (22 कैरेट) 54800, अलौह-धातु (किलो): कॉपर सी स्क्रैप 730, कॉपर एच स्क्रैप 720, कॉपर आरमेचर 706, कॉपर शोट कटिंग 518, ब्रास यूटेन्सिल स्क्रैप 491, एल्यू. यूटेन्सिल स्क्रैप 170, गुन मेटल स्क्रैप 520, ब्रास हनी 500, कॉपर बिलेट्स &, एल्यू. इंगट 207, ज़िंक इंगट 225, लेड इंगट 185, टिन इंगट 2420, निकिल केथड 1843, कॉपर सीसी रॉड 775 कौटन यार्न (किलो): कांडेड वायर: (10/1) &, (40/1) 245/250, (46/1) 255/260, (60/1) 260/265, देशी घो (प्रति लीटर): अमूल 580, विजया 640, पारस प्रौ. &, कुण्णा 495, गोकुल 590, परम प्रौ. 530, मधु सुदन 530, सोमेट (50

किलो/53 ग्रेड): अल्ट्राटैक 380, एससी 380, ग्रासिम &, वासव दत्ता 375, अम्बुजा उड़ीसा (320 नं.) 670/690, (400 नं.) 640, (240 नं.) 770/780, जेएच 680, बादामगिरी: कारमल 680, केलि. 660/680, लम्बी सिनोरा 700, किशमिश: कंधारी 300/410, ईडिबन 180/230, गोल्डन 200/220, मखाना 400/700, पिस्ता: बड़ा 1475/1575, पेशावरी 1825/1925, हैराती 2025/2125, नमकीन 1000, मगज तरबूज 700/720, केसर (प्रति ग्राम) 135/155, सफेद मूसली 1000/1400, अखरोट 200/375, जायफल 620/630, जालिन्डी कोचीन 65500/67500, मॉडियम 67500/68500, बेस्ट 72000/73000, खसखस 1000/1350, बड़ी इलायची 950/1100, इलायची हरी 1250/2150, लौंग 990/1100, दालचीनी 260/280, जायफल 620/630, जालिन्डी कोचीन 1600/1650, सिंगापु्र 1900/1950, अजवायन मॉडियम 150/170, धनिया खड़ा मॉडियम 78/92, मेथीदाना 80/82, मेवे: कaju (240 नं.) 770, (320

नं.)670/680, (300 नं.) 620, एसएडब्ल्यू &, कaju-डुकड़ी 440/590, उड़ीसा (320 नं.) 670/690, (400 नं.) 640, (240 नं.) 770/780, जेएच 680, बादामगिरी: कारमल 680, केलि. 660/680, लम्बी सिनोरा 700, किशमिश: कंधारी 300/410, ईडिबन 180/230, गोल्डन 200/220, मखाना 400/700, पिस्ता: बड़ा 1475/1575, पेशावरी 1825/1925, हैराती 2025/2125, नमकीन 1000, मगज तरबूज 700/720, केसर (प्रति ग्राम) 135/155, सफेद मूसली 1000/1400, अखरोट 200/375, जायफल 620/630, जालिन्डी कोचीन 65500/67500, मॉडियम 67500/68500, बेस्ट 72000/73000, खसखस 1000/1350, बड़ी इलायची 950/1100, इलायची हरी 1250/2150, लौंग 990/1100, दालचीनी 260/280, जायफल 620/630, जालिन्डी कोचीन 1600/1650, सिंगापु्र 1900/1950, अजवायन मॉडियम 150/170, धनिया खड़ा मॉडियम 78/92, मेथीदाना 80/82, कटिवाला 5300/5400,

जयपुर दाल (जीएसटी अतिरिक्त): मूंग मोगर 8900/9000, मोटा 9700/9800, उड़द 10000/10200, मोटा 10400/10500, चोलामोगर 7900/8000, मूंग मोगर 8000/8100, मूंग दाल छिलका देशी 8500/9500, मंगली 13500/14000, हल्दी राजासूरी 21000/24500, लालमिचं 25000/35500, कालीमिचं (किलो) 690/800, चॉनिया 9500/13500, जीरा 67500/78000, अजवायन 24500/42000, सोंफ 31500/50000, मेथी 8300/8400, एनएनएस

मुंबई | मंगलवार, 1 अगस्त 2023

बिज़नेस स्टैंडर्ड

एसबीआई ने जुटाए 10,000 करोड़ रुपये

अभिजित लेले

मुंबई, 31 जुलाई

देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने 15 साल के इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड से 10,000 करोड़ रुपये जुटाए हैं। इसकी कूपन दर 7.54 प्रतिशत है, जिसे जापान के केंद्रीय बैंक की सख्ती के कारण प्रतिफल घटने के बीच बेहतर दर माना जा रहा है। एसबीआई के अधिकारियों ने कहा कि 7.54 प्रतिशत तय प्रतिफल इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉन्डों की 7.7 प्रतिशत प्राइसिंग की तुलना में कम है, जो बैंक ने जनवरी 2023 में जारी किए थे।

पिछले सप्ताह जहां बाजार प्रतिफल बढ़े हैं, इसका असर 15 साल के इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड की पेशकश के मूल्य पर नहीं पड़ा है। एसबीआई के अधिकारियों ने कहा कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व की कार्रवाई और बैंक ऑफ जापान के रुख से 10 साल के सरकारी बॉन्ड के प्रतिफल को सीमित किया है। एस्बीआई ने एक बयान में कहा कि 7.54 प्रतिशत कूपन से सरकार की प्रतिभूति (जी-सेक) के वक्र से 13 आधार अंक का प्रसार नजर आता है। इसके पहले बैंक ने इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉन्डों से जनवरी 2023 में 9,718 करोड़ रुपये जुटाए थे, जिसमें प्रसार 17 आधार अंक था।

इसका बड़ा इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड दिसंबर 2022 में जारी हुआ था। बैंक ने 7.51 प्रतिशत कूपन दर से 10,000 करोड़ रुपये जुटाए थे। बॉन्ड की अवधि 10 साल की थी। घरेलू क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा बैंक की स्थिर परिदृश्य के साथ एएए क्रेडिट रेटिंग है। बॉन्ड से मिली राशि का इस्तेमाल दीर्घावधि संसाधन बढ़ाने में होगा जिससे बुनियादी ढांचे व सस्ते आवास के लिए वित्तपोषण किया जाएगा।

इस बॉन्ड पेशकश में दो घटक हैं। पहला आधार इश्यू 5,000 करोड़ रुपये का है और 5,000 करोड़ रुपये का ग्रीन शू ऑप्शन है। एसबीआई ने कहा कि इस इश्यू को निवेशकों से जोरदार प्रतिक्रिया मिली है , जिन्होंने 21,698 करोड़ रुपये की बोली लगाई और आधार इश्यू के आकार की तुलना में 4.34 प्रतिशत ओवर सब्सक्राइव हुआ। कुल 115 बोलियां मिलीं, जिससे व्यापक हिस्सेदारी के संकेत मिलते हैं। इसमें भविष्य निधि, पेंशन फंड, बीमा कंपनियों, म्युचुअल फंडों, कॉर्पोरेट्स आदि के हिस्सेदार शामिल हैं।

बीएस सूडोकू 4731									
		8			3				
		2		1					
6					1				
2					3	4	9		
	4			6		3			
				9	1	7			
				5	7				
5		4				2			
	3				7		5		

कैसे खेलें ?	आसान
हर रो, कॉलम और 3 के बाई 3 के बॉक्स में 1 से लेकर 9 तक की संख्या भरे।	★ ★ ★ ★

डिव्सलेमर, बिजनेस स्टैंडर्ड में प्रकाशित समाचार रिपोर्ट और फीचर लेखों के माध्यम से बाजारों, कॉर्पोरेट जगत और सरकार से जुड़ी घटनाओं की निष्पक्ष तत्वीर पेश करने का प्रयास किया जाता है। बिजनेस स्टैंडर्ड के नियंत्रण एवं जानकारी से परे परिस्थितियों के कारण वास्तविक घटनाक्रम भिन्न हो सकते हैं। समाचार पत्र में प्रकाशित रिपोर्टों के आधार पर पाठकों द्वारा किए जाने वाले निवेश और लिए जाने वाले कारोबारी निर्णयों के लिए बिजनेस स्टैंडर्ड कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। पाठकों से स्वयं निर्णय लेने की अपेक्षा की जाती है। बिजनेस स्टैंडर्ड के सभी विज्ञापन सद्भाव में स्वीकार किए जाते हैं। इनके साथ बिजनेस स्टैंडर्ड न तो जुड़ा हुआ है और न ही उनका समर्थन करता है। विज्ञापनों से संबंधित किसी भी प्रकार का दावा संबंधित विज्ञापनदाता से ही किया जाना चाहिए।
नै. बिजनेस स्टैंडर्ड प्रा. लि. का सर्वाधिकार सुरक्षित है बिजनेस स्टैंडर्ड प्रा. लि. से लिखित अनुमति लिए बोर समाचार पत्र में प्रकाशित किसी भी सामग्री का किसी भी तरह प्रकाशन या प्रसारण अतिषिद्ध है। किसी भी व्यक्ति या वैधानिक निकाय द्वारा इस प्रकार का निषिद्ध कार्य किए जाने पर दिवानी और फौजदारी कार्यवाही शुरू की जाएगी।

